<u>भागवत कथा - 3</u>

सविता (M.com.)-सरिता (B.Ed.)

यह एक और साहसिक कार्य है दो कन्याओं का- 29 साल की सविता सिंह और उनकी ही छोटी बहन सरिता सिंह उम्र 25 वर्ष। दोनों बी.एड्. पढ़ी हुई हैं। मुरलियों की ज्ञान की गहराई समझ, दोनों बहनों ने अपने पिता को मनाने की बहुत **लंबे समय तक कोशिश की** । आ.ई.वि.वि. परिवार के साथ रहकर ज्ञान के तंत सीखने-सिखाने की उनकी चाहत को उनके पिता ने ठुकरा ही दिया था । **सारी** कोशिशें फ़ेल होने पर दोनों बहनों को सामने कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था । तो उन्होंने अपना ईश्वरीय सेवाओं के लिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में समर्पित होने का निर्णय बताते हुए अपने पिता को एक पत्र लिखा और पत्र को घर में छोड़ अपनी राह कांपिल्य नगरी की तरफ़ दिनांक 27-08-2006 को पकड़ ली।

<u>Bhagawat Story - 3</u>

<u>Savita-Sarita:</u>

This is about another adventure of two kanyas (girls); Miss. Savita Singh aged 29 years and her Miss. Sarita Singh aged 25 years. Both completed B.Ed; Having come to know and grasped the depth of knowledge, both the sisters tried their best to convince their father for quite a long time; their intense wish to be at AVV for learning as well teaching the secrets of knowledge was denied outright by their father. With all their efforts having faced failure, no alternative was left before them; they proceeded towards Kampil on 27th August, 2006; leaving a letter addressed to their father at home indicating their intention.

दोनों बहनों के पिता और उनके चाचा कंपिल स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आ करके उनके ऊपर **अपने साथ अपने शहर सतना (मध्य प्रदेश) ले जाने के लिए दबाव डालने लगे**। उनकी धमकियों और दबावों पर दोनों कन्याओं ने कुछ ध्यान नहीं दिया।
Their father and his brother, i.e., the uncle of the girls have approached the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya at Kampil, and resorted to pressurizing their daughters to follow them to Satna in M.P. Both the sisters adhered to their decision while refuting their threats.

उसी दिन देर रात अर्थात दिनांक 31-08-2006 को पुलिस डी.एस.पी. विपुल कुमार श्रीवास्तव ने एस.एच.ओ. आदित्य प्रकाश यादव और ए.एस.आई. सुभाष चंद्र यादव और कंपिल व कायमगंज थाने के 30-40 पुलिस कॉन्स्टेबल्स को साथ ले करके कंपिल आध्यात्मिक विद्यालय पर छापा मारा । पुलिस

वाले कैसे दरवाज़े तोड़कर अंदर घुसे और कैसे कन्याओं-माताओं एवं भाइयों के साथ मार-पीट की, कैसे उत्पात मचाया- ये सारे विवरण बताते हुए शिखा बहन ने न्यायिक मैजिस्ट्रेट, कायमगंज के सामने केस **फ़ाइल** किया।

The D.S.P Vipulkumar Srivastav along with the SHO of the Kampil Poiice station Aditya Prakash Yadav, the A.S.I Subhash Chandra Yadav, along with a 30-40 constables from Kampil and Kaimganj stations, raided the "AVV" Kampil on the same night, i.e., on 31st August, 2006 at the odd hour in the night. Sikha bahan, one of the sisters of the Kampil "AVV" had filed a complaint before the Judicial Magistrate, Kaimganj describing the havoc created by the Police officials in the "AVV" ; as to how the police had broke opened the Main door of the "AVV"; beaten and tortured the girls, mothers and brothers.

पुलिस ने अपना बचाव करने के लिए उक्त छापे के बाद सविता-सरिता के पिता द्वारा सविता-सरिता को बंधक बनाने की व वीरेन्द्र देव दीक्षित द्वारा जान से मारने की धमकी देने की झूठी एफ.आई.आर. थाने में दर्ज करा दी, जो कि बाद में पुलिस को अन्तिम रिपोर्ट दाखिल कर बंद करनी पड़ी; क्योंकि सविता-सरिता अगर कोर्ट में जाकर बयान देती तो पिता का झूठ पकड़ में तो आना ही था।

To make up and save themselves post the raid, the police have got an false FIR registered in the Kampil Police Station against the residents of "AVV" with charges of captivity and threatening to kill the girls by Virendra Deo Dixit. And the police were left with no other alternative to submit a final report and close it down. Otherwise the false report compiled through their father would have to face light if Savita and Sarita submit a true statement before the court.

यह थी सविता-सरिता की पहली जीत।

This was the first victory for Savita and Sarita.

न्यायिक मैजिस्ट्रेट, कायमगंज के सामने शिखा बहन ने जो कम्प्लेंट-पत्र दाखिल किया था, उसे खारिज करने के कारण पुलिस वाले सेफ़ हो गए। अब केस को सत्र न्यायाधीश, फ़र्रुखाबाद के सामने ले जाना ही पड़ा।

The police had found themselves in a safety position when the complaint of sister Shikha was rejected outright by the Judicial Magistrate, Kaimganj. Now the case had to come before the Sessions Judge, Farrukhabad inevitably.

अब इस लिखत को आगे नहीं बढ़ाएँगे; परंतु दिनांक 10-05-2007 के फ़र्रुखाबाद के सत्र न्यायाधीश की जजमेंट के कुछ मुख्य अंश ज़रूर **नीचे पेश करेंगे**, जिससे सारी बातें खुद-ब-खुद क्लीयर हो जाएँगी। इसमें शिखा बहन की कम्प्लेंट भी दी गई है, जिनमें पुलिस वालों की गैरकानूनी हरकतें भी मौजूद हैं और फ़र्रुखाबाद के सत्र न्यायाधीश का आदेश भी मौजूद है।

At this stage, we do not advance this write up; instead, we prefer to directly mention some observations and order of the District and Sessions court, Farrukhabad, in their order 10th May, 2007, the contents are very much self-explicit of the facts and circumstances. The order is very much clear as to the contents of the complaint lodged by Sikha Bahan as to how the Police has created havoc in the Ashram. Extracts from the order of the Sessions Judge are also appended.

''न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फ़र्रुखाबाद।

समक्ष : श्री सर्वेश कुमार पांडेय एच.जे.एस.

फौजदारी निगरानी संख्या : 104/2007

कु. शिखा निगरानीकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी

निर्णय

यह निगरानी, निगरानीकर्ता कु. शिखा ने आदेश दिनांकित 21-03-2007 से उत्पीड़ित होकर प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, कायमगंज ने धारा 156 (3) प्रार्थना-पत्र ख़ारिज करने के संबंध में पारित किया।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक प्रार्थना-पत्र धारा 156 (3) जा.फौ. के अंतर्गत शिखा बहन ने अपर न्यायालय के सम्मुख अंतर्गत धारा 147,148,149,452,323, 427, 342, 504, 506 भा.द.सं. व 29 पुलिस एक्ट के अंतर्गत विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, कायमगंज, फ़र्रुखाबाद, आदित्य प्रकाश यादव थानाध्यक्ष कंपिल फ़र्रुखाबाद, सुभाषचंद्र यादव उपनिरीक्षक कंपिल फ़र्रुखाबाद व 30-40

पुलिस कर्मचारीगण जिनको सामने आने पर पहचान सकते हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 31-08-2006 को रात करीब 7-8 बजे पुलिस उपाधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव अपने अधीनस्थ आदित्य प्रकाश यादव, थानाध्यक्ष कंपिल और उपनिरीक्षक सुभाषचंद्र यादव कम्पिल व 30-40 पुलिस कर्मियों को लेकर आए और दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। कारण पूछने पर उपरोक्त पुलिस कर्मियों तथा साथ आए अन्य पुलिस कर्मियों ने कु. सरिता एवं सविता बहन के बारे में पूछा, जिनकी वार्ता विद्यालय के अंदर लगी सीखचों की खिड़की में से उपरोक्त पुलिस कर्मियों से कराई गई तथा सरिता और सविता ने अपने संलग्न प्रपत्र दिखाए और पुलिस कर्मियों से कहा कि वह बालिग हैं और अपनी मर्ज़ी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रही हैं; लेकिन उपरोक्त पुलिस कर्मी इस बात पर आमादा हो गए कि कु. ***सविता*** *एवं सरिता रात में थाने में चलें और वहीं निपटारा होगा। कोई महिला उपरोक्त पुलिस कर्मियों के साथ नहीं थी। प्रार्थिनी व कु. सविता, सरिता एवं आश्रम की अन्य माताओं व बहनों तथा भाइयों ने उपरोक्त पुलिस कर्मियों से कहा- रात बीत जाने दो, सुबह थाने आ जाएँगे।*

लेकिन थानाध्यक्ष कंपिल आदित्य प्रकाश यादव व सुभाष चंद्र यादव उपनिरीक्षक थाना कंपिल व अन्य पुलिस कर्मी, उपाधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में नहीं माने तथा आश्रम का गेट ज़बरन तोड़ने लगे। सभी पुलिस कर्मी आश्रम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आए। सभी पुलिस कर्मियों ने आश्रम की माताओं, बहनों तथा भाइयों को लात-घूसों व डंडों से मारा। बहनों-माताओं तथा भाइयों को आश्रम में ही बंधक बना लिया। पूरे आश्रम की तलाशी ली।

पृष्ठ-2

भाइयों को आश्रम में ही मुर्गा बनाया तथा उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया। यह कार्यक्रम करीब दो घंटे तक चलता रहा। पुलिस कर्मियों ने यह भी धमकी दी कि आश्रम खाली करके चले जाओ; नहीं तो कंपिल कस्बे में बहनों-भाइयों को दौड़ा-2 कर पीटा जाएगा तथा आश्रम खाली करवाया जाएगा तथा 10 से 30 हज़ार रुपये तक नुकसान हुआ तथा माताएँ व बहनें सामूहिक रूप से बेइज़्ज़त हुईं। यह भी कहा है कि पुलिस द्वारा की गई मार-पीट से बहन प्रमिला, शकुंतला, शैला तथा भाई सुनील एवं भाई सिद्धेश घायल हुए थे, जिनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। यह भी कहा है कि बहन कु. सविता एवं सरिता ने दिनांक 02-09-2006 को प्रार्थना-पत्र मय शपथपत्र पंजीकृत डाक से पुलिस अधीक्षक, फ़तेहगढ़ व पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र कानपुर, पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र कानपुर को पंजीकृत डाक से भेजे गए; लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा न्यायालय से वाद दर्ज कर विवेचना करने की प्रार्थना की गई तथा प्रार्थना-पत्र के साथ शपथपत्र व अन्य साक्ष्य तथा चिकित्सीय रिपोर्ट प्रमिला, कु. शैला, शकुंतला, सुनील कुमार व सिद्धेश कुमार की प्रस्तुत की गई तथा फोटो आदि भी पेश किए गए।

विधान अपर न्यायालय ने उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई करते समय यह पाया कि प्रार्थना-पत्र में प्रकरण संज्ञेय अपराध का कारित होना नहीं प्रतीत होता है और प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया तथा अपर न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पुलिस का यह कार्य ऐसा था जिसे करने के लिए उक्त पुलिस अधिकारीगण विधि द्वारा आबद्ध थे। इस प्रकार पुलिस द्वारा आश्रम में घुसने का कृत्य आपराधिक अतिचार की श्रेणी में नहीं आएगा बल्कि पुलिस अधिकारी अपने कार्य की प्रकृति के अनुरूप उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत थे अथवा आबद्ध थे।

उक्त आदेश (21-03-2007) से उत्पीड़ित होकर यह निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अपर न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत नहीं है और अपर न्यायालय का आदेश अवैधानिक है। अतः निगरानी स्वीकार की जाए।

मैंने उभयपक्ष के विधान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अध्ययन किया।

मेरे समक्ष निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित सिद्धांत पर विश्वास व्यक्त किया गया है।

<u>1983 क्राइम्स पृष्ठ-914 शंभू बी.एस. बनाम टी.एस. कृष्ण स्वामी</u> :-

उपरोक्त वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब कोई संपन्न किए गए शिकायती कार्य, जो न्यायिक अधिकारी द्वारा किया गया है और उसके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के मध्य नहीं है, वहाँ न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के लिए अभियोजन चलाया जा सकता है। इसके लिए धारा 197 जा.फौ. के अंतर्गत कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

पृष्ठ-3---- सर्वप्रथम उल्लेखनीय है कि जो तथ्य वर्णित किए गए हैं, वे किसी भी पुलिस कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किए जाने योग्य नहीं माने जा सकते हैं तथा प्रार्थना-पत्र को पढ़कर एक संज्ञेय अपराध कारित होना प्रतीत होता है तथा अपर न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है कि पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया कार्य जो कि न्यायानुमत है; विधि सम्मत नहीं है और विधि विरुद्ध है तथा मनमाने ढंग से निकाला गया निष्कर्ष है। धारा 156 (3) प्रार्थना-पत्र के लिए न्यायालय को यह देखना है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध कारित हुआ अथवा नहीं और पुलिस द्वारा कोई वाद दर्ज किया गया अथवा नहीं

मेरे विचार में अपर न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधि विरुद्ध है तथा अवैधानिक है। अतः निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश :</u>

निगरानी स्वीकार की जाती है । आदेश दिनांकित 21-03-2007 निरस्त किया जाता है । अपर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह पुनः धारा 156(3) के प्रार्थना-पत्र पर पक्षकारों को सुनकर ऊपर दिए गए निर्देशों के प्रकाश में विधि सम्मत निष्कर्ष निकाले।

पक्षकार दिनांक 17-05-2007 को अपर न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हों ।

*दिनांकः **10-05-2007*** *सर्वेश कुमार पांडेय*

सत्र न्यायाधीश, फ़र्रुखाबाद ।

उक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया ।

दिनांकः 10-05-2007 *सर्वेश कुमार पांडेय*

सत्र न्यायाधीश, फ़र्रुखाबाद। ''

In the Court of Sessions Judge, Farrukhabad.

In the presence of Shri Sarvesh Kumar Pandey, H.J.S

Appeal No. 104/2007

Miss Sikha Plaintiff

vs

Uttar Pradesh State Respondent

"Aggrieved by the order of the Jujdicial Magistrate, Kaimganj dated 21-03-07, whereby the petition of the appellant has been rejected under section 165 (3), the appellant Miss. Sikha has approached this court. The facts of the case are as under. "A petition u.s. 156(3) has been filed in the presence of Judicial Magistrate, under sections, 147, 148, 149, 452,323, 427,342, 504, 506 of CRPC and 29 of Police Act in respect of Sri Vipul Kumar Srivasta, D.S.P., along with (i) Aditya Prakash Yadav, SHO, Kampil., (ii) Subhas Chandra Yadav, A.S.I., and 30 to 40 other Police Staff who could be identified when they come in presence.

On the night of 31-08-06 Sri Vipul Kumar Srivasta, S.P., alongwith (i) Aditya Prakash Yadav, SHO, Kampil., (ii) Subhas Chandra Yadav, A.S.I., and 30 to 40

other Police Staff with PAC came to Kampil Ashram at around 7-8 P.M., and asked to open the doors.

On being asked for the reason, the above Police officers and other police staff have enquired about Sarita and Sarita. They were produced for a talk through the grilled windows. Sarita and Savita have shown their papers to them and told them that they are majors and getting the Spiritual knowledge as per their will. But the above mentioned Police Officials got annoyed and asked Sarita and Savita to follow them for Police Station during that night at which place the matters would be disposed. No lady police was present in the above mentioned Police staff. The appellant along with Sarita and Savita, other sisters and brothers have requested the police; let the night go and we shall come to the police station in the morning.

But, Aditya Prakash Yadav, SHO, Kampil., Subhas Chandra Yadav, A.S.I., and other Police Staff under the leadership of Sri Vipul Kumar Srivasta, D.S.P., have not accepted and started breaking the doors forcibly. All the Police staff intruded inside and resorted to beating the sisters, matas and brothers with wrists and lathis. The Police have detained the sisters, matas and brothers in the ashram itself. They searched the entire premises.

Page-2: The brothers were made to crawl on the floor and the police have behaved indecently with them. The process continued for more than two hours. The Police also threatened the inmates to vacate the ashram and get away, otherwise they would be chased and thrashed in the village. The devastation caused by the Police amounted to a loss of 10 to 30 thousands in terms of money in addition and the mothers and sisters were subjected to defamation. It was also said that sisters Pramia, Shakuntala, Shaila and brothers Sunil and Sidhdhesh were injured. A medical examination was conducted for them. It was also said that requests and affidavits were sent to S.P. Fategarh, D.I.G., Kanpur range and I.G., Kanpur by registered post on 02-09-2006. The Police remained inactive. The court is requested to pass necessary orders. Affidavits, other evidences and medical reports of Miss Pramila, Shaila, Shakuntala, Sunil Kumar and Sidhdhesh and the photos etc, along with the request were submitted.

While hearing the petition, the Judicial Magistrate Court, Kaimganj has rejected the petition with an observation that the episode described mentioned in the petition does not appear to be a cognizable offence. The court has further ordered that the act of the Police officials in intruding the Ashram forms part of their duties and responsibilities and does not fall in the category of the crime but the police

officials were duty-bound to act in such a way by virtue of the responsibilities entrusted to them and by virtue of Law of land.

Aggrieved with the above order dated 21-03-2007, this appeal has been filed on the ground that the order of the Kaimganj court is not in accordance with law and stands illegal. So, the appeal may please be accepted. ”

I have heard the arguments of the learned advocates and gone through the documents submitted. The undernoted case has been relied on behalf of the appellants in my presence……1983 Crimes Page 914 Shambhu B.S. Vs T.S. Krishna Swamy: In the above case, the Honorable Supreme Court has approved the theory that Where an investigation has been done in the case of crime and if that does not form part of the Government duties, there the allegations framed against the investigating officer can be prosecuted. No authority is required for this purpose under section 197 supra.

Page-3: Firstly it is to be mentioned that the facts stated herein do not warrant to be done by any Police Staff during the course of discharge of his duties and a study of the petition reveals the existence of a cognizable crime and the conclusion arrived at by the kaimganj court that the act resorted to by the Police official is legal, is not legal and against Law and the conclusion arrived at the whims. The court in respect of the petition under section 156(3) has to see whether any one has committed a cognizable crime or not and any dispute has been raised by the police in this regard or not.

In my opinion, the judgment delivered by the Kaimganj Court is fully against law and illegal and hence the appeal is eligible to be allowed.

ORDER: The appeal is allowed. The order dated 21-03-07 is cancelled. The Kaimganj court is ordered to hear the news media in respect of the petition under section 156(3) and arrive at the conclusion according to law in the light of the above order. The news media is advised to be present before the Kaimganj Court on 17-05-2007.

Dated 10-05-2007 Sarvesh Kumar Pandey, Sessions Judge. Farrukhabad.

The above decision and order has been announced in the open court and signed by me. Dated 10-05-2007 Sarvesh Kumar Pandey, Sessions Judge. Farrukhabad.”

फ़र्रुखाबाद के सत्र न्यायाधीश के आदेशनुसार कन्याओं-माताओं के प्रति अमानवीय और राक्षसी हरकतों का संगीन अपराध किए हुए पुलिस वालों की सफ़ेद और रंगीन रूप में पब्लिश की गई न्यूज़ मीडिया की कुछ हेडलाइंस नीचे दी गई हैं।

तारीख	न्यूज़ मीडिया	विभिन्न अखबारों की न्यूज़ हेडलाइंस
01-09-06	अमर उजाला	लड़कियाँ बरामदगी को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में छापा-मामला संगीन : फ़र्रुखाबाद के कंपिल में काफ़ी नोक-झोंक के बाद पुलिस दरवाज़ा तोड़ अंदर घुसी
01-09-06	अमर उजाला	लड़कियाँ नहीं मिलीं, पुलिस ने घेर रखी है पूरी इमारत ; आश्रम की शिष्या ने कहा- पिता के साथ नहीं जाना चाहतीं ; पिता के जबरन ले जाने की धमकी पर कहीं भाग गईं
02-09-06	अमर उजाला	पलटवार-शिष्याओं ने कराया मेडिकल ; क्या होगा : पुलिस कार्रवाई को देखने के लिए उमड़ी स्थानीय लोगों की भीड़ -फोटो अमर उजाला ; अफ़सरों पर मुकदमा कराया जाएगा-वकील
02-09-06	अमर उजाला	स्वेच्छा से ज्ञान प्राप्त करने आते हैं-शिखा बेन ; छापा मारकर अव्यवस्था फैला दी-प्रमिला बहन ; ज्ञान में बाधा डाली जा रही-सीमा बेन ; बेटे को प्रताड़ित कर रही पुलिस-राजकुमारी ; आश्रम में गलत काम नहीं होता-विपिन कुमार
02-09-06	अमर उजाला	लोहिया अस्पताल में मेडिकल करातीं ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिष्याएँ और शिष्य। फोटो-अमर उजाला
02-09-06	दैनिक जागरण	आश्रम प्रबंधन ने न्यायालय जाने का ऐलान किया ; मानवाधिकार आयोग में भी मामले को उठाएँगे बाबा के चेले ; पाँच घायलों का मेडिकल

पुलिस वालों को फ़र्रुखाबाद के सत्र न्यायाधीश ने उनकी गलती का एहसास तो करा दिया। अब पुलिस कर्मियों को सज़ा दिलाने की बात जहाँ तक रही, भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है; बल्कि ड्रामा प्लैन अनुसार स्वभावतः सारे कार्य होते हैं।

Some news headings of the news media published in white and colored in respect of the inhuman, indecent, shameful and destructive acts of the Police on innocent girls and mothers of the "AVV" which were declared as cognizable offense by the Sessions Court, Farrukhabad are appended.

Amar Ujala 01-09-2006

The search and seizure of the girls from Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya. The matter cognizable. The police broke the doors and intruded into the Ashram after a long squabble.

Amar Ujala 01-09-2006

The girls could not be traced. Police surrounded the entire Ashram. The student of the Ashram said; the girls did not want to go along with their father. They escaped for the threats by their father to take them along with him.

Amar Ujala 02-09-2006

In reciprocation-The students got medical test done. What is going to happen? Huge gathering of local people to observe the actions of Police. Photo-Amar Ujala-Case will be filed against the Officers-Advocate.

Amar Ujala 02-09-2006

The students come to ashram at their own will- Said sister Sikha – The system disturbed by search and seizure-Sister Pramila-The knowledge is being disrupted-Sister Seema. The children are harassed by Police-Rajkumari-No untoward deeds happen in the Ashram-Vipul Kumar.

Amar Ujala 02-09-2006

Photo-The girls and other students of Ishwariya Vishwa Vidyalaya getting medical test done.

Dainik Jagaran 02-09-2006

The management of the Ashram declared to approach the Court. The students of Baba will raise the issue before Human rights commission-Medical test of the five injured.

The Sessions Judge of the Farrukhabad Court has made the police realize their blunders. As far the punishment accordable to the Police is concerned, Spiritual Brother Virendra Deo Dixit need not do anything further. Instead, the law will take its own course in respect of all the future happenings.

अब शिखा बहन की कम्प्लेंट को जिस निचली कोर्ट के मैजिस्ट्रेट ने खारिज किया था, उनको फिर फ़र्रुखाबाद के सत्र न्यायाधीश के आदेश का अनुपालन करना ही पड़ा । तो फिर से केस निचली कोर्ट में माननीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट, कायमगंज के सामने पहुँच गया।

Now it has become incumbent for the lower court which has rejected the complaint of sister shikha to honour the order of the Higher Court. In the circumstances the case was reverted to the Judicial Magistrate for necessary action.

माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने केस में संज्ञान लेकर अभियुक्त/आरोपी विपुल कुमार श्रीवास्तव, आदित्य प्रकाश यादव व सुभाष चन्द्र यादव को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया। लेकिन बार-2 सम्मन भेजने के बावजूद उक्त पुलिस गण सारे हथकंडे अपनाते हुए लम्बे समय तक न्यायालय में हाज़िर नहीं हुए। जिसके परिणामस्वरूप माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने सभी अभियुक्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट (गैर जमानती वारंट) जारी कर उनकी सैलरी को भी अटैच करने का आदेश दिया। लेकिन सभी अभियुक्त पुलिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से तथ्यों को छिपाते हुए एक पक्षीय स्टे ऑर्डर ले लिया। उक्त स्टे ऑर्डर को खारिज करने के लिए शिखा बहन व सविता-सरिता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में विरोधी पक्ष के खिलाफ लम्बी लड़ाई लड़ी व सन 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों पुलिस कर्मियों के स्टे ऑर्डर को खारिज किया व पुलिस कर्मियों के द्वारा दाखिल की हुई स्टे ऑर्डर की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 20.05.2016 द्वारा खारिज कर दिया।

The Honorable Magistrate having taken the order in to cognizance has summoned the accused Vipul Kumar Srivastav, Aditya Prakash Yadav and Subhas Chandra Yadav, to be present in the court in his presence. Despite summoning repeatedly by the Magistrate, the police group avoided to appear before the court on different pretexts from time to time. In result, the Magistrate had served non-bailable warrant on the respective police staff and ordered to attach their salaries. However, the said accused police staff could obtain stay order from the Allahabad High Court while hiding the facts. And Shikha bahan has fought it out the case in the

Allahabad High Court for long and the Allahabad High Court has in turn cancelled the stay order against the three accused vide their order dated 20-05-2016.

शिखा बहन, सविता-सरिता व विद्यालय के अन्य भाई-बहनों के बयानों के आधार पर यह हुई सरिता-सविता की दूसरी जीत।

Based on the courageous statements of the spiritual sisters shikha bahan, Savita and Sarita and other sisters and brothers, this stood the second victory for Sarita and Savita.

उसके बाद यह सच्चाई की लड़ाई आज भी सरिता-सविता व शिखा बहन द्वारा जारी है; क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते, भले ही उसके लिए प्राण भी क्यों न चले जाएँ। ''देहं वा पातयामि, कार्यं वा साधयामि''।

And in subsequence, the war for the rescue of Truth is still on through Sarita-Savita and Shikha Bahan, for the Man of high morale do not leave any task unfinished, well the life be lost! The task will be solved ; let the body lose its life. Some extracts relating to the case are annexed.

इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं |

पुलिस प्रपत्र सं०

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

मुक संख्या

मु० अ० सं० - 329/06 धारा 343-506 I.P.C. थाना - कायमगंज

फर्रुखाबाद

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

... की धारा 154 के अन्तर्गत ... अपराध की प्रथम सूचना

कायमगंज

कायमगंज

फर्रुखाबाद — 27-8-06 — समय कदम तहरीर

77/06

... समय जब रिपोर्ट की गई	घटना स्थान ...	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन
दि - 31-8-06 समय 21-10 P.M.	प्रजापति ... नालेज ...	शुक्रवार

... सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना चाहिए और इसकी गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा होनी चाहिए।

... देने वाले वादी ... निवास	अभियुक्त का नाम व निवास स्थान	...	तहकीकात के संबंध में जो कार्यवाही की गई ... दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
			४	५
[illegible] E-W-S-24 ... 9300938412 ... 31-8-06 ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 2191.06

... सूचना पृष्ठ ... में लिखी जायेगी।

... सूचना ... हस्ताक्षर ...

C.O.

क्षेत्राधिकारी कायमगंज

जनपद फर्रुखाबाद

नकल तहरीर हिन्दी वादी मुन्दरजा रपट तारीख 31-8-06

सेवा में श्रीमान थाना - इन्चार्ज महोदय थाना - कम्पिल फर्रुखाबाद उ.प्र.
दिनांक 31-8-06 निवेदन है कि प्रार्थी की दो बालिग पुत्रियां जिनमें
बड़ी कु० सावित्री सिंह एम. काम. बी.एड. एवं इसकी कु० सारिका सिंह एम.
काम. बी. एड. [illegible] हैं। ये दोनों ग्राम कम्पिल में स्थित
आश्रम रामेश्वर मन्दिर जैन मन्दिर देखने के लिये कहकर
26-8-06 को घर से चली थी जिनको तारीख 29-8-06 तक वापस
आ जाना था। उन दोनों के न लौटने पर मैं अपनी बहन
मीना सिंह व [illegible] सिंह ग्राम कम्पिल आया यहाँ के [illegible]
मन्दिर धर्मशाला कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर मन्दिर तलाश
करते हुए आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय कम्पिल पहुंचा
तो मुझे अपनी दो बेटियों की मौजूदगी की जानकारी मिली। उनसे
आग्रह करने पर संचालिकाओं ने खिड़की से बात कराई। [illegible]
मिलने पर दोनों बेटियाँ भयभीत व असहाय स्थिति में होने की जानकारी
सारिका ने कहा कि हमें यहाँ तारीख 28-8-06 से बन्धक बना
कर आध्यात्मिक पूजा के नाम पर रखा हुआ है हमें कैसे
भी यहाँ से मुक्त करा के [illegible] यहाँ से ले लो। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] संचालिकाओं
से आग्रह किया [illegible] [illegible] [illegible] के लिये
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] मेरी दोनों
पुत्री [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] बहादुर सिंह [illegible] कालोनी [illegible]
[illegible] मो० - 9300938[illegible] दिनांक 31-8-06

नोट: - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की गयी

[illegible]
थाना - कम्पिल
फ़र्रुखाबाद
दि० 31-8-06

अंतिम रिपोर्ट NO

थाना [illegible] प्रथम सूचना संख्या 17/06 तारीख 31-8-06 (वादी की [illegible]) जिला [illegible]

थाना [illegible] अंतिम रिपोर्ट संख्या 13/06 तारीख 18/9/06

1- वादी या सूचना देने वाले का नाम और पता	श्री [illegible] [illegible] [illegible] महाराष्ट्र प्रदेश [illegible] [illegible]
2- शेष अभियोग का स्वरूप	
3- [illegible] (यदि कोई हो)	
4- अभियुक्त [illegible] नाम और पता (यदि कोई हो)	[illegible]
5- [illegible]	[illegible] दिनांक 31-8-06 [illegible]
6- [illegible]	
7- [illegible]	

थाना कविनगर
जिला [illegible]

[illegible]
18/9/06

थाना कविनगर
जिला [illegible]

Typed Copy

जिला– फर्रूखाबाद	प्रथम सूचना रिपोर्ट 77/06	तारीख 31/08/06
थाना– कम्पिल	अंतिम रिपोर्ट संख्या 13/06	तारीख 18/09/06

33

1– वादी या सूचना देने वाले का नाम पता	श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह S/o श्री वेंकटस्वर प्रताप सिंह R/o बन्धवगढ़ कालोनी E-W-S 24 सतना मध्य प्रदेश।
2– दोष या अभियोग का स्वरूप	धारा 343/506 आई0पी0सी0 P/S कम्पिल
3– चुरायी गयी सम्पत्ति का विवरण यदि कोई हो	
4– अभियुक्त व्यक्तियों के नाम व पता यदि कोई हो	संचालिकाये
5– यदि गिरफ्तारी की गयी है व गिरफ्तारी का दिनांक	श्रीमान जी
6– मुक्त किये जाने का दिनांक व	निवेदन है कि दिनांक 31/08/06 को समय करीब 21.10 पी0एम0 पर मुकदमा वादी खाता

प्र.प्र.कृ. हर्ष

समय क्या जमानत पर या मुचलका पर छोड़ा। 7– सम्पत्ति हथियारों सहित जो पायी गयी हो किसने वहां पायी तथा किस मजिस्ट्रेट के पास भेजी गयी। 8– संक्षेप में प्रथम सूचना या अभियोग पुलिस कार्यवाही या परिणाम सहित विवरण। 9– अन्य विवरण	नं01 ने थाने पर तहरीरी मुकदमा उपरोक्त कायम कराया। विवेचना मुझ एस0आई0 के सुपुर्द की गयी दौराने विवेचना दो लड़कियों कुमारी सविता व सरिता के द्वारा दिये गये शपथ में लड़की हाईस्कूल की मार्कशीट में अंकित जन्मतिथि व बयनों के आधार पर दो लड़की बालिग है। एक की उम्र 28 व दूसरी 25 साल की है। वालिग है। अपनी मर्जी से शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रजापति ईश्वरी विश्व विद्यालय में अपनी मर्जी से आयी थी किसे का दबाव नहीं है। और न संचालिकाओं ने बंधक बनाया है से संबंधित का होना जुर्म खारिज किया जाता द्वारा FR विवेचना समाप्त की जाती है। रिपोर्ट प्रेषित है।

CHANDRA PRAKASH
07/2013
1/5/13

न्यायालय श्रीमान जे०एम० महोदय कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद 55

Case No. 597/09.

कु०शिखा बनाम विपुल कुमार

11/02/2010

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुयी।

यह प्रार्थना पत्र परिवादिनी ने इस आशय का दिया है कि आध्यत्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कस्बा कम्पिल में स्थित है। जहां आध्यत्मिक ज्ञान दिया जाता है। दिनांक 03/08/06 को रात्रि 7–8 बजे पुलिस अधीक्षक श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव अपने अधीनस्थ थानाध्यक्ष आदित्य प्रकाश यादव व उपनिरीक्षक सुभाषचन्द्र यादव हथियानों के साथ 30–40 पुलिस कर्मियों को लेकर आये और दरवाजा खोलने को कहा कारण पूछने पर पुलिस कर्मियों ने कुमारी सरिता एवं सविता बहन के बारे में पूछा जिनकी वार्ता अंदर से लगी सीखचों की खिड़की में से पुलिस कर्मियों से करायी गयी। और कहा कि वह वालिग है। तथा अपनी मर्जी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रही है। उक्त पुलिस कर्मी इस बात पर आमादा हो गये कि कुमारी सरिता व सविता रात में थाने में चले और वही निपटारा होगा। कोई महिला पुलिस कर्मियों के साथ नहीं थी। प्रार्थिनी व कुमारी सविता सरिता एवं आश्रम की अन्य माताओं व बहनों तथा भाइयों ने पुलिस कर्मियों से कहा रात बीत जाने दो सुबह थाने आ जायेंगे। लेकिन उपरोक्त पुलिस कर्मचारीगण ने माने और आश्रम का गेट जबरन तोड़ने लगे और पुलिस कर्मी अंदर घुस आये और लात घुसों व डण्डों से मारा और आश्रम में ही बंधक बना दिया और सभी को बेइज्जत किया यह कार्यकम करीब दो घंटे तक चला और कहा कि तीन दिन थे आश्रम खाली करके चलें जाओ और पुलिस की तोड़ फोड़ से करीब 10,000 सें 30,000 रू० का नुकसान हुआ। उस समय केवल पुलिस कर्मी और आश्रम के निर्दोष बहने मातायें ही आश्रम में मौजूद थी सभी का सामूहिक रूप से उत्पीड़न किया गया। पुलिस द्वारा की गयी मारपीट से बहन प्रमीला शकुंतला, शैला तथा भाई सुनील व भाई सिद्वेश घायल हुये थे। जिनका चिकित्सीय परीक्षण अस्पताल फर्रूखाबाद के आकस्मिक चिकित्साधिकारी द्वारा किया गया था। इस सम्पूर्ण प्रकरण के संबंध में दैनिक समाचार पत्र एवं अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं हुयी। तो प्रार्थिनी ने दिनांक 13/09/06 को राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार 4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली को आवेदन किया। फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुयी तब यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

Scanned by CamScanner

56

परिवादिनी ने धारा 200 द0प्र0सं0 के अंतर्गत स्वयं को परीक्षित किया है। और धारा 202 द0प्र0सं0 के अंतर्गत पी0डब्लू01 सरिता पी0डब्लू02 शैला पी0डब्लू03 प्रासीला पी0डब्लू04 सविता पी0डब्लू05 शकुंतला, पी0डब्लू06 सुनील कुमार को परीक्षित कराया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी ने विपक्षीगण पर घर में घुसकर लात घुसों व डण्डों से मारपीट कर गाली गलौज करने व तोड़फोड़ करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। परिवादिनी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 में परिवाद पत्र के तथ्यों का समर्थन किया है तथा न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 202 द0प्र0सं0 में की गयी जांच की कार्यवाही में परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत समई साक्षियों के बयानों से परिवादिनी द्वारा रखे गये केस के तथ्यों को बल मिलता है। परिवादनी द्वारा रखे गये केस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से विपक्षीगण के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला धारा 323,452,427 504 506 भा0द0सं0 के अंतर्गत बनता हुआ प्रतीत होता है। अतः अभियुक्तगण उक्त धाराओं में तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण विपुल कुमार श्रीवास्तव पुलिस उपाधिक्षक कायमगंज आदित्य प्रकाश यादव थानाध्यक्ष कम्पिल सुभाषचन्द्र यादव उपनिरीक्षक कम्पिल जनपद फर्रूखाबाद को धारा 323,452 427 504 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्तगण बजरिये समन तलब हो। परिवादिनी पैरवी अविलम्ब करें। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 12/03/2010 को पेश हो।

Sd-

जे0एम0कायमगंज

प्रतिलिपि कर्ता

12/03/10

पुकार करायी गयी। परिवादिनी गैर हाजिर। अभि0गण गैर हाजिर जरिये समन दिनांक 17/04/10 को तलब हों। पैरवी की जाये।

Sd-

जे0एम0कायमगंज

17/04/10

पुकार करायी गयी। परिवादी के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध वारंट जारी करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पेश होकर आदेश हुआ कि सुना पत्रावली का अवलोकन किया। अभि0गण पर तामीला शुदा समन संलग्न पत्रावली नहीं अब निरस्त किया जाता कि अभि0गण जरिये समन दिनांक 26/05/10 को तलब हो।

Scanned by CamScanner

Mob : 9415360973

Yogendra Kumar Srivastava

Advocate, High Court

Resi. 220 MIG Preetam Nagar, (near Kohli Dhaba), Allahabad.

Seat No. 179
(In front of Chamber No.39)
High Court, Allahabad.

Criminal misc. Application No.- 15328 - OF 2016

(DISTRICT- Farrukhabad

Vipul Kumar Srivastava ---------------- Petitioner (s)

// Versus //

State of U.P. and others ---------- Respondent (s)

ORDER DATED- 20-5-2016

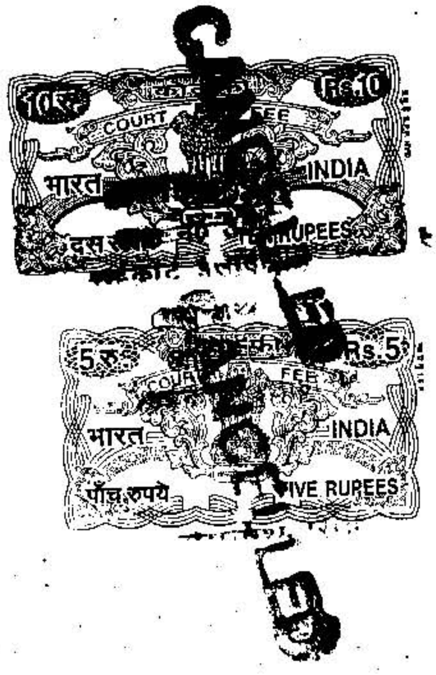

Court No. - 55

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 15328 of 2011

Applicant :- Vipul Kumar Srivastava
Opposite Party :- State Of U.P. And Another
Counsel for Applicant :- Siddhartha Srivastava,Rakesh Kumar Upadhyay
Counsel for Opposite Party :- Govt.Advocate,Yogendra Kr.Srivastava

Hon'ble Karuna Nand Bajpayee,J.

This application under Section 482 Cr.P.C. has been filed seeking the quashing of impugned order dated 29.6.2009 passed by Judicial Magistrate, Kayamganj, Farrukhabad as well as entire proceeding in Case No. 597 of 2009 arising out of Case Crime No. 3006 of 2007, under Sections 147, 148, 149, 452, 323, 427, 342, 504 & 506 IPC Police Station Kampil District Farrukhabad pending in the court of Judicial Magistrate,Kayamganj, Farrukhabad.

List has been revised. Despite repeated calls none has appeared on behalf of the applicant to press this application. Shri Amol Kokane and Shri Y.K. Srivastava, learned counsel for the opposite party no. 2 are present along with learned AGA. This application is of year 2011.

Perusal of the ordersheet reveals that on 18.5.2015, as a last opportunity two weeks and no more time was given to the learned counsel for the applicant for filing rejoinder affidavit and it was specifically observed by the Court that no adjournment shall be granted on the ground of illness slip. Today again an illness slip has been sent by the learned counsel for the applicant.

In the wake of heavy pendency of cases in this Court where dockets are already bursting on their seams there is no justifiable reason to further procrastinate the matter. This Court, therefore, deems it fit to proceed in the matter on the basis of the record and with the assistance of the learned AGA representing the State.

The perusal of the grounds taken in the application on behalf of the applicant indicates that mostly relates to the disputed questions of

fact. The impugned order dated 29.6.2009 reflects judicial application of mind. It appears that the final report was submitted by the police but the Protest Petition was filed on behalf of the applicant in which several allegations about the unfair investigation was made on behalf of the complainant. The Court below after going through the relevant aspects of the matter deemed it fit to treat the Protest Petition as a complaint case and took the cognizance in the matter.

It goes without saying that this is very much within the rights of the Court below to treat the Protest Petition as a complaint case and it has been rightly done so by the Court below. There is no reason to take a different view in the matter. The Court below has also rejected the final report and taken cognizance of the matter under Section 190 (1)(a) of Cr.P.C. If in the opinion of the Court the case diary contained sufficient material, the Court below could have proceeded to summon the accused to face trial but that option has not been exercised obviously for the reason that the investigation itself was believed to be highy flawed. Another option of taking cognizance under Section 190 (1)(a) of Cr.P..C. has been exercised by the Court below. In the considered opinion of this Court, the impugned order cannot be faulted with. There is no illegality or abuse of the Court's process reflected in the impugned proceeding.

Therefore, this application is devoid of merit and the same stands dismissed as such.

Order Date :- 20.5.2016

CPP/-

AUTHENTICATED COPY
23-6-16
SECTION OFFICER
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT ALLAHABAD

Mob : 9415360973

Yogendra Kumar Srivastava

Advocate, High Court

Resi. 220 MIG Preetam Nagar, (near Kohli Dhaba), Allahabad.

Seat No.179
(In front of Chamber No.39)
High Court, Allahabad

Criminal misc application - No: 21395 - OF 2016

(DISTRICT- Farrukhabad

Aditya Prakash Yadav .... Petitioner (s)

// Versus //

State of U.P. and other .... Respondent (s)

ORDER DATED- 20-5-2016

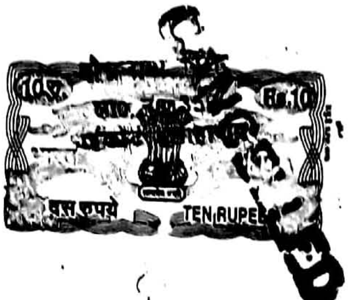

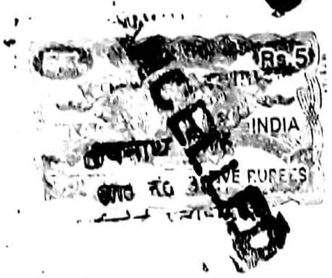

Scanned by CamScanner

Court No. - 55

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 21395 of 2011

Applicant :- Aditya Prakash Yadav
Opposite Party :- State Of U.P. And Another
Counsel for Applicant :- Rishi Kant Rai,R.K. Upadhyay
Counsel for Opposite Party :- Govt.Advocate,Smt. Anita Srivastava

Hon'ble Karuna Nand Bajpayee,J.

This application under Section 482 Cr.P.C. has been filed seeking the quashing of impugned orders dated 11.2.2010 and 16.6.2011 passed by the Judicial Magistrate, Kayamganj, Farrukhabad as well as entire proceeding in Complaint Case No. 597 of 2009 under Sections 323, 452, 427, 504,506 IPC Police Station Kampil District Farrukhabad pending in the court of Judicial Magistrate, Kayamganj, District Farrukhabad.

List has been revised. Despite repeated calls none has appeared on behalf of the applicant to press this application. Shri Amol Kokane and Shri Y.K. Srivastava, learned counsel for the opposite party no. 2 are present along with learned AGA. This application is of year 2011. In the wake of heavy pendency of cases in this Court where dockets are already bursting on their seams there is no justifiable reason to further procrastinate the matter. This Court, therefore, deems it fit to proceed in the matter on the basis of the record and with the assistance of the learned AGA representing the State.

The perusal of the grounds taken in the application, though not of much help, reveal that many of them relate to disputed questions of fact. The court has also been called upon to adjudge the testimonial worth of prosecution evidence and evaluate the same on the basis of various intricacies of factual details which have been touched upon on behalf of applicant. The veracity and credibility of material furnished on behalf of the prosecution has been questioned and false implication has been pleaded. The submissions raised in the application on behalf of the applicants call for adjudication on pure questions of fact which may be adequately adjudicated upon only by the trial court and while doing so even the submissions made on points of law can also be more appropriately gone into by the trial court in this case. This Court does not deem it proper, and therefore cannot be persuaded to have a pre-trial before the actual trial begins.

The law regarding sufficiency of material which may justify the summoning of accused and also the court's decision to proceed against him in a given case is well settled. The court has to eschew itself from embarking upon a roving enquiry into the last details of the case. It is also not advisable to adjudge whether the case shall ultimately end in conviction or not. Only a prima facie satisfaction of the court about the existence of sufficient ground to proceed in the matter is required.

Through a catena of decisions given by Hon'ble Apex Court this legal aspect has been expatiated upon at length and the law that has evolved over a period of several decades is too well settled. In the case of **Chandra Deo Singh Vs. Prokash Chandra Bose AIR 1963 SC 1430** the Apex Court had observed as follows:-

"The courts have also pointed out in these cases that what the magistrate has to see is whether there is evidence in support of the allegations of the complainant and not whether the evidence is sufficient to warrant a conviction. The learned Judges is some of these cases have been at pains to observe that an enquiry under Section 202 is not to be likened to a trial which can only take place after process is issued, and that there can be only one trial. No doubt, as stated in sub-section (1) of Section 202 itself, the object of the enquiry is to ascertain the truth or falsehood of the complaint, but the magistrate making the enquiry has to do this only with reference to the intrinsic quality of the statements made before him at the enquiry which would naturally mean the complaint itself, the statement on oath made by the complainant and the statements made before him by persons examined at the instance of the complainant."

In the yet another case of **Vadilal Panchal Vs. Dattatraya Dulaji Ghadigaonker AIR 1960 SC 1113** the Hon'ble Supreme Court had expressed the views in the following terms:

"Section 202 says that the magistrate may, if he things fit, for reasons to be recorded in writing, postpone the issue of process for compelling the attendance of the person complained against and direct an inquiry for the purpose of ascertaining the truth or falsehood of the complaint; in other words, the scope of an inquiry under the section is limited to find out the truth or falsehood of the complaint in order to determine the question of the issue of process. The inquiry is for the purpose of ascertaining the truth or falsehood of the complaint; that is, for ascertaining whether there is evidence in support of the complaint so as to justify the issue of process and commencement of proceedings against the person concerned. The section does not say that a regular trial for adjudging the guilt or otherwise of the person complained against should take place at the stage; for the person complained against can be legally called upon to answer the accusation made against him only when a process has issued and he is put on trial."

In the case of **Smt. Nagawwa Vs. Veeranna Shivalingappa Konjalgi 1976 3 SCC 736** the Hon'ble Apex Court had held as follows:

"The magistrate has been given an undoubted discretion in the matter and the discretion has to be judicially exercised by him. Once the magistrate has exercised his discretion it is not for the High Court, or even this Court, to substitute its own discretion for that of the magistrate or to examine the case on merits with a view to find out whether or not the allegations in the complaint, if proved, would ultimately end in conviction of the accused. These considerations, in our opinion, are totally foreign to the scope and ambit of an inquiry under Section 202 of the Code of Criminal Procedure which culminates into an order under Section 204 of the Code. Thus it may be safely held that in the following cases an order of the magistrate issuing process against the accused can be quashed or set aside:

(1) where the allegations made in the complaint or the statements of the witnesses recorded in support of the same taken at their face value make out absolutely no case against the accused or the complaint does not disclose the essential ingredients of an offence which is alleged against the accused;

(2) where the allegations made in the complaint are patently absurd and inherently improbable so that no prudent person can ever reach a conclusion that there is sufficient ground for proceeding against the accused;

(3) Where the discretion exercised by the magistrate in issuing process is capricious and arbitrary having been based either on no evidence or on materials which are wholly irrelevant or inadmissible; and

(4) where the complaint suffers from fundamental legal defects, such as, want of sanction, or absence of a complaint by legally competent authority and the like.

The cases mentioned by us are purely illustrative and provide sufficient guidelines to indicate contingencies where the High Court can quash proceedings."

The Apex Court decisions given in the case of **R.P. Kapur Vs. State of Punjab AIR 1960 SC 866** and in the case of **State of Haryana Vs. Bhajan Lal 1992 SCC(Cr.) 426** have also recognized certain categories by way of illustration which may justify the quashing of a complaint or charge sheet. Some of them are akin to the illustrative examples given in the above referred case of **Smt. Nagawwa Vs. Veeranna Shivalingappa Konjalgi 1976 3 SCC 736.** It was observed by the Hon'ble Apex Court in Bhajan Lal's case as follows:-

"The following categories can be stated by way of illustration wherein the extra-ordinary power under Article 226 or the inherent powers under Section 482 of the Code of Criminal Procedure can be exercised by the High Court either to prevent abuse of the process of any Court or otherwise to secure the ends of justice, though it may not be possible to lay down any precise, clearly defined and sufficiently channelised and inflexible guidelines or rigid formulae and to give an exhaustive list of myriad kinds of cases wherein such power should be exercised:

(1) where the allegations made in the First Information Report or the complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their entirety do not prima facie constitute any offence or make out a case against the accused.

(2) where the allegations in the First Information Report and other materials, if any, accompanying the F.I.R. do not disclose a cognizable offence, justifying an investigation by police officers under Section 156(1) of the Code except under an order of a Magistrate within the purview of Section 155(2) of the Code.

(3) where the uncontroverted allegations made in the FIR or complaint and the evidence collected in support of the same do not disclose the commission of any offence and make out a case against the accused.

(4) where the allegations in the FIR do not constitute a cognizable offence but constitute only a non-cognizable offence, no investigation is permitted by a police officer without an order of a Magistrate as contemplated under Section 155(2) of the Code.

(5) where the allegations made in the FIR or complaint are so absurd and

inherently improbable on the basis of which no prudent person can ever reach a just conclusion that there is sufficient ground for proceeding against the accused.

(6) where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the Code or the concerned Act (under which a criminal proceeding is instituted) to the institution and continuance of the proceedings and/or where there is a specific provision in the Code or the concerned Act, providing efficacious redress for the grievance of the aggrieved party.

(7) where a criminal proceeding is manifestly attended with mala fide and/or where the proceeding is maliciously instituted with an ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and personal grudge."

Illumined by the case law referred to herein above, this Court has adverted to the entire record of the case.

A threadbare discussion of various facts and circumstances, as they emerge from the allegations made against the accused, is being purposely avoided by the Court for the reason, lest the same might cause any prejudice to either side during trial. But it shall suffice to observe that the perusal of the complaint, and also the material available on record make out a prima facie case against the accused at this stage and I do not find any justification to quash the complaint or the summoning order or the proceedings against the applicant arising out of them as the case does not fall in any of the categories recognized by the Apex Court which may justify their quashing.

The prayer for quashing the same is refused as I do not see any abuse of the Court's process either.

The application is accordingly, dismissed. The interim order, if any, is vacated.

Order Date :- 20.5.2016

CPP/-

AUTHENTICATED COPY
23.06.2014
SECTION OFFICER / A. R.
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT ALLAHABAD

Mob : 9415360973

Yogendra Kumar Srivastava

Advocate, High Court

Resi. 220 MIG Preetam Nagar, (near Kohli Dhaba), Allahabad.

Seat No.179
(In front of Chamber No.39)
High Court, Allahabad

Criminal misc Application- No:- 26423 - OF 2016

(DISTRICT- Farrukhabad

Subhash Chandra ---------------- Petitioner (s)

// Versus //

State of U.P. and other ------------ Respondent (s)

ORDER DATED- 20-5-2016

Court No. - 55

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 26423 of 2011

Applicant :- Subhash Chandra
Opposite Party :- State Of U.P. And Another
Counsel for Applicant :- Dur Vijay Singh
Counsel for Opposite Party :- Govt.Advocate,Smt. Anita Srivastava

Hon'ble Karuna Nand Bajpayee,J.

This application under Section 482 Cr.P.C. has been filed see quashing of criminal proceedings in Case No. 597 of 2009, u Sections 323, 452,427,504 & 506 IPC Police Station Kampil Di Farrukhabad pending in the court of Judicial Magistrate,Kayam Farrukhabad.

Heard Shri Dur Vijay Singh, learned counsel for the applicant and Amol Kokane and Shri Y.K. Srivastava, learned counsel for the opp party no. 2 are present along with learned AGA. This application is of 2011.

Perusal of the grounds taken in the application on behalf of the appli indicates that mostly relates to the disputed questions of fact, w requires detailed appreciation of evidence which can be done only du the course of trial.

Further submission of learned counsel for the applicant is that the f report has been wrongly rejected and the Court below has wrongly tre the Protest Petition as a Complaint Case, therefore, the impug proceeding going on, against the applicant deserves to be quas Learned counsel for the applicant has tried to show that the appli being government servant should not be prosecuted like this, as the done by him were in discharge of his official duties.

Learned counsel for opposite party no.2 and the learned AGA h opposed prayer made in the application.

It appears that after submission of the final report, the Court be adverted to the facts of the case and as the allegations were made that investigation was not fair, the Court below preferred to treat Pro Petition as a Complaint Case and took cognizance in the matter ur *Section 190(1)(a) of Cr.P.C. In the considered opinion of this Court,* i

course adopted by the Magistrate was perfectly within the permissible limit. If the case diary did not contain enough material on the basis of which the cognizance could have been taken under Section 190 (1)(b) of Cr.P.C. then this option was very much available for the Magistrate to treat the Protest Petition as a Complaint Case and, therefore, the impugned order cannot be faulted with. So far as question of discharge of official duties is concerned, it is settled law that under the grab of discharge of official duties the offences can not be allowed to be committed by the officia. This is not a question of dereliction of duty. The alleged offence committed by the applicant prima facie, does not appear to be under the protection and the same cannot be said to be done in discharge of official duties. Even, this matter has to be finally adjudicated upon after going through the entire evidence and at this stage, a final finding about this aspect of the matter is difficult to arrive at. If after the entire evidence is produced during the course of trial, the Court below comes to the conclusion that the conduct or acts done by the applicant were in discharge of his official duties, then this advantage may be given by the Court below to the applicant at a later stage also. The evidence produced on behalf of the complainant was duly considered by the Court below and it was found by the Court that there were sufficient grounds to proceed against the accused on the basis of evidence that was produced during the course of enquiry. Prima facie, allegations made are sufficient to constitute offence against the applicant and, therefore, the impugned proceeding cannot be faulted with.

It is settled law that the standard of sufficiency of evidence in order to summon the accused to face trial is different from appreciation of evidence which is to be applied at the final stage for deciding the case. This Court in exercise of its inherent jurisdiction can not have a pretrial before the actual trial begins. The impugned order does not reflect any illegality or abuse of the Court's process, therefore, the prayer to quash the same can not be accepted.

The interim order, if any, is vacated.

However, it is observed that if the bail has not been obtained as yet, the accused may appear before the court below and apply for bail within **two** months from today. The court below shall make an endeavour to decide

the bail application on the same day, if possible, keeping in view the observations made by the Court in the Full Bench decision of **Amrawati and another Vs. State of U.P. 2004 (57) ALR 290** and also in view of the decision given by the Hon'ble Supreme Court in the case of **Lal Kamlendra Pratap Singh Vs. State of U.P. 2009 (3) ADJ 322 (SC).**

In the aforesaid period or till the date of appearance of the accused in the court below, whichever is earlier, no coercive measures shall be taken or given effect to.

With the aforesaid observations this application is finally disposed off.

Order Date :- 20.5.2016

CPP/-

AUTHENTICATED COPY
23.6.2016
SECTION OFFICER
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT ALLAHABAD